


आदेश-पत्रक

(ऐसे अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक - ता०..... से..... तक
 जिला..... सं०..... सन् १९.....
 केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे टिप्पणी, तारीख-सहित ३
<p>12.07.2013 <u>2-8-13</u></p>	<p>न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा</p> <p>भूमि विवाद अपील वाद संख्या 64/2012</p> <p>मो० नुरुलआवदीन — अपीलार्थी वनाम</p> <p>पिकी कुमारी एवं अन्य — प्रत्यर्थागण</p> <p>प्रस्तुत अपील वाद मो० नुरुलआवदीन पिता - स्व० अमीर हसन ग्राम -सिमरी बख्तियारपुर, थाना- बख्तियारपुर जिला- सहरसा द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, सिमरीबख्तियारपुर के आदेश दिनांक 23.01.12 अन्दर वाद संख्या 81/11 के विरुद्ध दाखिल किया गया है।</p> <p>निम्न न्यायालय में दिनांक 23.06.2011 को दायर वाद में वादी का कथन है कि वर्ष 1928 में वादी के नानी ने दो केवाला से जमीन खरीदी जो सिडुल में वर्णित है। सिडुल 'क' में वादी के नानी को मसोमात सुरति ने जो विक्री किया है वह है सिडुल 'ख' वादी के नानी ने मोहन साह से जमीन 7 कट्टा 10 धुरकी खरीदी जो विवाद का विषयवस्तु नहीं है। वादी के दखल कब्जा वाली जमीन जिसे सिडुल "ख" में वर्णित है प्रतिवादी नं० 3 से 8 के पूर्वज मोहन साह से 1928 में जमीन खरीद है। जो विवाद का विषय वस्तु नहीं है। वादी के पूर्वज को 7 कट्टा 10 धुरकी एवं 10 कट्टा जमीन मोहन साह से 1928 में खरीदा है, पहले केवाला मोहन साह किया, जिसमें पश्चिम सुरति मासोमात दिया है। 1928 में ही उसी दिन सुरति मसोमात से वादी की नानी ने जमीन खरीदी जो 10 कट्टा है। इसी 10 कट्टा जमीन जो मोहन गुप्ता से पश्चिम है जिसे नवाव साहब ने सड़क सीधा करने के लिए मो० सुरति वाला खरीद जमीन में करीब 2 कट्टा जमीन में सड़क बन गया । सुरति वाली 10 कट्टा जमीन में बने सड़क ने जमीन को पूरब एवं पश्चिम भाग में बांट दिया। यही पश्चिम वाला भाग 03 कट्टा जमीन मोकदमा हाजा का विषयवस्तु है जिसे सिडुल "ग" में दिखाया गया है जो सिडुल "क" का अंश है।</p> <p>यह भी कथन है कि प्रतिवादी नं०-1 एवं 2 के ससुर ने इसी मोकदमा हाजा वाली जमीन को पहले नन्दकेश्वर शर्मा से लिखाया प्रस्तुत वाद में श्री उपेन्द्र प्रसाद सेवा अवकाश शिक्षक है जो प्रतिवादी नं०1 एवं 2 के खास ससुर है , खुद के नाम जमीन खरीदा पुनः उसी जमीन को दिगर लोगों से केवाला अपने पोतोहू पतिवादी नं०1</p>	

एवं 2 के नाम कराया जबकि धारा 144 दं0 प्र0 सं0 का मामला लूबित के दौरान जमीन केवाला कराया गया है। धारा 144 दं0 प्र0 सं0 का कोई आदेश 60 दिन के भीत जाने पर प्रभावहीन हो जाता है।

यह भी कथन है कि प्रतिवादी नं01 एवं 2 प्रतिवादी 3 से 8 से जमीन खरीदा है इसलिए उन्हें पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी नं01 एवं 2 के पतिगण मिलकर प्रतिवादी नं09 एवं 10 तथा दिगर के हाथ जमीन का कागजात बनाकर उलझन खड़ा करना चाहता है इसलिए उन्हें भी पक्षकार बनाया गया है। मामला भूमि विवाद का है जिसमें वादी इस न्यायालय से प्रतिवादी नं01 एवं2 के द्वारा केवाला नं0 908 दिनांक 28.02.11 को खरीदा गया है उसी वजह से यह नालीस किया जाता है।

वादी का यह भी कथन है कि उन्हें जमीन अपने मां से मिला उनकी मां को जमीन अपनी मां से यानि नानी से मिला। वादी की मां के नाम जमीन का जमाबंदी दर्ज है जिसका रसीद कटता है। जमाबंदी नं0 1190 है। वादी के पिता के गुजर जाने पर वादी की मां ने दूसरी शादी की जिन्हें कोई संतान नहीं हुआ वो बिना संतान के फौत कर गये।

वादी का यह भी कथन है कि जमीन पश्चिम है जो केवाला मोहनलाल साह का बोलता है जो प्रतिवादीगण से संबंधित है फिर किस प्रकार प्रतिवादी वादी का 03 कट्टा जमीन पश्चिम तरफ से हड़पना चाहता है जिसका प्रयास दिनांक 22.01.11 को किया, जिसके विरुद्ध धारा 144 दं0 प्र0 सं0 की चली उसमें प्रतिवादी नं0 3,7, एवं 5 के पक्ष में फैसला गया जिस फैसला के विरुद्ध की0 री0 नं0 40/11 विद्वान सत्र न्या0 में लंबित है।

वादी का यह भी कथन है कि 01.11.0.0. (एक बीधा ग्यारह कट्टा) जमीन किसी भी सुरत पर प्रतिवादीगण को प्राप्त नहीं था न उनकी खतियानी थी बल्कि बन्दोबस्ती से थोड़ा -2 जो जितना अलग अलग खरीदे उतने पर दखलकार हुए वो जरूरत पड़ने पर बिक्री कर दिए। इसलिए खतियानी कुल रकबा को बटवारा कर व हिस्सा बराबर गंगा साह वो मोहन साह वा कल्दू साह में होने की बात गलत है। प्रतिवादी गण का कोई सराकार उक्त उक्त सिडुल की जमीन में नहीं है बल्कि प्रतिवादी नं0 3 से 8 के पूर्वज को जमीन जो भी प्राप्त था वह बिक्री कर दिया उन्हें इस खेसरा में बिक्री के बाद एक इंच जमीन नहीं बचा, जिसका प्रमाण स्वयं प्रतिवादी गण नं0 3 से 8 के पूर्वज द्वारा किया गया केवाला साक्ष्य के रूप में है लिस्ट सबूत के साथ दाखिल किया गया है। सिडुल 'ख' की नानी ने निबंधित केवाला संख्या 4499 दिनांक 22 सितम्बर 1928 में मोहनलाल साह प्रतिवादी नं0 3,4,5,6,7,8 के पूर्वज से खरीदी है जिस पर वादी दखलकार है। दखलकार के आधार पर वादी के नाम खतियान इन्द्राज है। प्रतिवादीगण सिडुल 'ग' की जमीन से वादी को किसी भी समय हटाने के लिए कानून को हाथ में लेने पर उत्तारू है जिसके लिए उक्त जमीन की खरीद बिक्री नहीं करने, कोई संरचना नहीं करने हेतु प्रतिवादी नं01 एवं 2 पर अन्तरिम निषेधाज्ञा लगाने हेतु वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमसरीबख्तियारपुर के न्यायालय में वाद दायर किया गया था।

प्रतिवादी प्रथम पक्ष संख्या 1 एवं 2 द्वारा लिखित जबाब के साथ दाखिल की गई। शेष प्रतिवादीगण 3,4,5,6,7 एवं 8 प्रतिवादी प्रथम पक्ष 1 एवं 2 के बिकेता हैं। लिखित जबाव में प्रतिवादी प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष का कथन है कि सिडुल "क" एवं "ख" की जमीन से कोई संबंध संरोकार नहीं बताते हुए मात्र सिडुल "ग" में वर्णित भूमि को

निबंधित दस्तावेज संख्या 908 दिनांक 28.02.11 से खरीदगी बताया है, तदनुसार खाता पुराना 348 खाता नया 224 खेसरा पुनाना 3963 खेसरा नया 6244 रकबा 8 डिसमल जिसका चौहद्दी - उत्तर: सोलिंग सड़क दक्षिण: उपेन्द्र ना0 प्रसाद, पुरब: पक्की सड़क, पश्चिम: केशरे हिन्द सड़क है पर प्रतिवादी नं01 एवं 2 का केवाला खरीदगी तिथि से अद्यतन दखलकार है। यह भी कथन है कि वाद खरीदगी केवाला के जमाबन्दी नं0 5089 नाम से पिकी कुमारी सिंह कायम करवा कर अद्यतन मालगुजारी रसीद वर्ष 2011-12 प्राप्त है एवं ईट की चहारदिवारी से प्रश्नगत विवादी भूमि घिरा हुआ है। जिसपर प्रतिवादी नं0 1 एवं 2 दखलकार हैं।

निम्न न्यायालय में पारित आदेश में कहा गया है कि मूल रूप से विवादी भूमि सिडूल "ग" की वर्णित भूमि मौजा - बख्तियारपुर थाना नं0 64 अंचल: सिमरीबख्तियारपुर, थाना: बख्तियारपुर, जिला: सहरसा के अन्तर्गत खाता 348 पुराना नया 224 खेसरा पु0 3963 नया 6244 रकबा 3 कट्टा जिसका चौहद्दी - उत्तर: सड़क सोलिंग, दक्षिण: 3959 खेसरा पुराना ,पूरब: पक्की सड़क, पश्चिम: केशरे हिन्द। प्रश्नगत भूमि है जिसे प्रतिवादी प्रथम पक्ष नं0: 1 एवं 2 द्वारा भी बताया गया है, लेकिन रकबा में भिन्नता है। वादी द्वारा तीन कट्टा रकबा बताया गया है, जबकि प्रतिवादी प्रथम पक्ष संख्या 1 एवं 2 के द्वारा 1 कट्टा 17 धूर रकबा बताया गया है। वादी द्वारा वर्णित चौहद्दी में पुराना खेसरा 3959 का उल्लेख वाद पत्र में किया गया है। इसके विपरीत उक्त चौहद्दी दक्षिण से उपेन्द्र ना0 प्रसाद को दर्शाया गया है। इस प्रकार दक्षिण चौहद्दी में रैयती भूमि होने की बात को उभय पक्ष द्वारा स्वीकार की गयी है। बाकी सभी तीन ओर से चौहद्दी की समानता वादी के रकबा को प्रमाणित करता है।

वादी के दाखिल दो केवाला वर्ष 1928 जो विवादी खेसरा पुराना 3963 का मूल आधार है का कायम जमाबन्दी नं0 1190 का कुल जमा रकबा 1-8-5-10 से संबंधित है के आधार पर वादी के केवाला खरीदगी वर्ष 1928 ई0 की भूमि का औचित्य प्रमाणित नहीं होता है। न्यायालय का मत है कि विवादी खेसरा पुराना 3963 नया खेसरा 6244 का रकबा 3 कट्टा भूमि जिसका उल्लेख सिडूल "ग" में किया गया है पर वादी का दावा प्रमाणित नहीं होता है। इसके विपरीत केवाला नं0 908 दिनांक 28.02.11 से संदर्भ प्रश्नगत विवादी भूमि खेसरा 3963 पुराना नया 6244 रकबा 1 क0 17 धूर अर्थात 08 डी0 भूमि पर पक्की ईट की चहारदिवारी से घेराबन्दी रहने के कारण दखल कब्जा की पुष्टि परिलक्षित होता है। वादी पक्षकार द्वारा कोई भी कागजी प्रमाण वर्ष 1928 ई0 की खरीदगी भूमि से कितनी जमीन सड़क के रूप में अर्जित की गई है, इसकी प्रमाणिकता का ठोस अभाव भी वादी के दाखिल अर्जी दावा पर प्रश्नवाचक चिन्ह उत्पन्न करता है। दाखिल अर्जी दावा में वादी द्वारा आशंकित बेदखली की आशंका से यह वाद दाखिल की गई है जबकि वादी की ओर से दाखिल कागजी प्रमाण से वादी का दावा प्रमाणित नहीं है।

कागजी प्रमाण, प्रमाण के आधार पर प्रश्नगत सिडूल "ग" की भूमि में प्रतिवादी नं0 1 एवं 2 का निर्विवाद हक एवं दखल मुताबिक खरीदगी केवाला के प्रमाणित है, जिस पर वादी पक्षकार को कुछ भी अधिकार एवं दखल नहीं है। वादी अपना अर्जी दावा सिद्ध करने में पूरी तरह से असफल रहे हैं। अतः वादी का अर्जी दावा अस्वीकृत की जाती है।

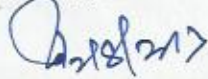
निम्नन्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 17.02.2012 को वाद दायर करते हुए कहा गया है कि आवेदक द्वारा टायटिल सूट नं0 23/93 जिसमें उपेन्द्र गुप्ता एवं तिलकधारी साह के वारिसान को भी पक्षकार बनाया गया था में डिग्री आवेदक के पक्ष में हुआ है । अतएव दिनांक 23.01.12 को निम्नन्यायालय के भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 81/12 में पारित आदेश निरस्त योग्य है।

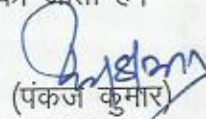
वादी/प्रतिवादी के विज्ञ अधिवक्ता का सुना । निम्नन्यायालय का अभिलेख तथा उभय पक्षों के लिखित बहस का अवलोकनोपरान्त यह तथ्य उभर कर सामने आया कि व्यवहार न्यायालय, सहरसा के अवर न्यायाधीश के इजलाश में दायर टायटिल सूट संख्या 23/93 में दिनांक 20.01.2013 को आदेश पारित किया गया है कि -

" The suit is decreed on contest with cost. The defendant number One is directed to hand over the possession of the disputed land to plaintiff within six months form the date of the judgment after removing his illegal constructions otherwise the plaintiff has to be the recourse to the law. "

वर्णित स्थिति में अपीलार्थी उक्त वाद में पारित आदेश को कार्यान्वित कराने हेतु व्यवहार न्यायालय में execution Suit दायर कर सकते हैं। अपीलवाद की कारवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित




(पंकज कुमार)

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा